

: 1 बाबुक्त (वपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा करबौरकेन्द्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE

द्वितीय तझ, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Raikot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in



DIN20230164SX000000EB89

अपील / फाइनसंख्या/ Appeal /File No. GAPPL/COM/STP/1368/2022 मूल आदेश मं / O.I.O. No. 01,02& 03/2021-22 दिनांक/Date 29-03-2022

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-131-2022

आदेश का दिनांक / Date of Order: 27.12.2022

जारी करने की तारीख / Date of issue:03.01.2023

बी शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपीस्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ मेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीघाम। द्वारा उपरमिखित जारी मूक आदेश ने सुजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

वपीनकर्ग &प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Digvijasinh P Gohil, 75/A, Shantinagar, B/H Press QuarterShivpaarvati, Street No. 3/4Bhavnagar

इस आदेश(अपीज) से व्यथित कोई व्यक्ति निभ्नितिश्वित तरीके में उपयुक्त प्राक्षिकारी / प्राक्षिकरण के समक्ष अपीच दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर व्यथितीय न्यायाधिकरण के प्रति अपीता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अञ्चिनियम , 1944 की बारा 35B के वर्तात (A) एवं विश्व अभिनियम, 1994 की बारा 86 के वर्तात निम्निविद वगह की जा सकती है।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मृत्यांकन से सम्बन्धित सभी भागमे सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीसीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, अतर के पुरेम, नई दिल्सी, की की जानी चाहिए।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बहाए गए अपीलों के बनावा शेष सभी अपीलें नीमा शुरूक,केंद्रीय उत्पाद शुरूक एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, ,द्वितीय तम, बहुमानी भवन असावा अहमवाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीक्षीय न्यायाधिकरण के सुमक्ष अपीक्ष प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुक्क (अपीक्ष) नियमावधी, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपष्ट EA-3 को चार प्रतियों में वर्ष किया जाता चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के लाभ, जहां उत्पाद शुक्क की माँग, ज्याज की माँग और स्नाया गया जुर्माना, रुपए 5 ताले या अपीक्ष, उत्पाद सुप्त के स्वया 50 लाक्ष या 50, काल या प्रति के साथ, उत्पाद के स्वया 50 लाक्ष या 5,000/- रुपये का निर्धारित जान शुक्क की प्रति संक्षप्त करें। निर्धारित शुक्क का मुगतान, मंबिधित अपीक्षीय न्यायाधिकरण की शाला के मुहायक रजिल्दार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के देक द्वारा जारी रेखांकित के प्रति प्राप्त मंबिधित अपीक्षीय न्यायाधिकरण की शाला किसी जाना चाहिए। संबंधित इपस्ट का मुगतान, वक्त की उस शाला में होना चाहिए जहां संबंधित अपीक्षीय न्यायाधिकरण की शाला क्षित है। स्थान आदेश (क्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुक्क जमा करना होगा।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst, Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

व्यपीलीय न्यायाविकरण के समक्ष अपील, विश्व अविनियम, 1994 की बारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निव्यपित प्रयम् 8.T,-5 में बार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उतके साथ जिस आदेश के विकद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और दरगय के मंग करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और दरगया गया जुर्माना, क्यर के साथ प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और दरगया गया जुर्माना, क्यर साथ प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और दरगया गया जुर्माना, क्यर का प्रमाण प्रति प्रमाण के प्रति प्रमाण के प्रति प्रमाण के अधिक है तो क्रमशं : 1,000/- क्यरे, 5,000/- क्यरे अपवा 10,000/- क्यरे का निश्चित जुर्म की प्रति संनग्न करें। निश्चित शृष्क का प्रशासन, मंगवित स्थापविकरण की शाला के सहाय रिजटार के नाम से किसी भी सार्वजिक्त केन के बेक द्वारा जागी रेखांकित बेक द्वारेट हारा किया जाना चाहिए। मंगवित इंग्स्ट का भुगतान, बेक की उस साला में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाला स्थित है। स्थान आदेश (स्ट ऑडरे) के जिए आवेदन-पत्र के नाथ 500/- रुपए का निश्चित शृक्त जमा करना होगा।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Massistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is little accompanied by a fee of Rs.500/-.

B)

वर्षाला

केन्द्रीय उर्द

(i)

(11)

भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण आवेदन ई कार्र, विशेष अपनित्र के क्षेत्र के के क्षेत्र के (C)

यदि मान के किसी नुक्तान के भामने में, जहां नुक्तान किसी मान को किसी कारवाने से संदार गृह के पारममन के दौरान या किसी बन्य कारवाने या किस किसी एक भंदार गृह से बुतरे भंदार गृह पारममें के दौरान, या किसी भंदार गृह में या महारच में बास के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारवाने या किसी भंदार गृह में मान के नुक्तान के मानके में / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे मास के बिनिर्माण में प्रयुक्त कड़ों मास पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुक्त के खुट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्वात की शरी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

विवे उत्पाद शुरूक का भुगदान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भुटान को मास निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के जत्पादन शुरू के मुगतान के लिए जो ड्यूटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आपक (अपीन) के द्वारा विश्व अधिनियम (क 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई सारीख अवशा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। किए गए हैं। Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतिवां प्रभव संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुक्क (सर्गोक्त) नियसावती 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्देष्ट हैं, इस आदेश के संघ्रय के अ नाह के अंदर्गत के जानी चाहिए। उपरोक्त कर्नेदन के साथ संबंध व अपीक्ष क्षेत्र की दो प्रतियां संबंध की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अधिनियम, 1944 की घारा 35-EE के तहत निर्वारित शुक्क की बदावनी के साथ्य के तौर पर TR-6 की प्रति संवध की जानी चाहिए। / The shove application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account. (v)

पुनरीक्षण खबेदन के साथ निम्निवित निर्धारित शुरूक की अंदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रक्ष एक बाख क्याये या उसते कम हो तो क्याये 200/- का सुगतान किया जाए और यदि संबग्न रक्षम एक बाख क्याये हे ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रलेक मूल अवेश के लिए शुरूक का मुगतान, उपर्युक्त दंग से किया जाना चाहिये। इस तब्य के होते हुए भी की जिला पढ़ी कार्य से बचन के लिए यद्यास्थिति संपीतीय न्यासिकरण को एक अपीत या कड़ीय सर्रकार को एक अवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various umbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeals to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथारंशोधित न्यायालय तुरुक अधितियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थान आदेश की पति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुरूक टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)

तीमा शुरूक, केन्द्रीय उत्पाद शुरूक एवं सेवाकर अपीतीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावसी, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामसों को सम्मिनित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीकीय प्राधिकारी को अपीक दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीक्षार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को वेस तकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filling of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website **www.obec.gov.in. (G)



STATE STATE IN ADDED IN ADDEA

M/s. Digvijaysinh P. Gohil, Bhavnagar (hereinafter referred to as "Appellant") has filed the present against since Order-in-Original No. 01, 02 & 03/2021-22 dated 29.03.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Superintendent, CGST Range-1, Central GST Division-1, Bhavnagar (hereinafter referred to as 'adjudicating authority'):

- 2. The facts of the case, in brief, are that on the basis of departmental audit, proceedings were initiated against M/s. Chandroday Cable Network, Bhavnagar (hereinafter referred to as "M/s. Chandroday") for evasion of service tax under the category of "Cable Operators Services". Proceedings were also initiated against sub-cable operators of M/s. Chandroday, including the Appellant, for non-payment of service tax by wrongly claiming benefit of value-based exemption under Notification No. 06/2005-ST dated 01.03.2005, despite providing services under other's brand name. These proceedings resulted in issuance of Show Cause Notices dated 16.04.2015, 16.03.2016 and dated 13.10.2017 for the period from April-2013 to March-2014, April-2014 to March-2015 and April-2015 to June-2017 to the Appellant proposing demand of service tax of Rs. 2,65,172/- including Education Cess and S.H. Education Cess along with interest and imposition of penalty under Sections 76, 77(1)(a), 77(2) and 77(1)(c) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as "the Act").
- 3. The Adjudicating Authority vide the impugned orders confirmed Service Tax demand of Rs. 2,65,172/- under Section 73(1) along with interest under Section 75 of the Act, imposed penalty not exceeding Rs. 2,65,172/- under Section 76 of the Act and penalty of Rs. 10,000/- each under Section 77(1)(a), 77(2) and 77(1)(c) of the Act.
- 4. Being aggrieved, the Appellant preferred present appeals contending, inter-alia, as under:
- (i) The impugned order is not correct as it has been passed without making legal interpretation of provisions of the Act. He was providing services as "Cable Operator" in relation to transmission of waives through electronically system independently and they has not provided taxable service by using the symbol/brand name of "Chandroday". His taxable value had not exceeded the threshold limit of Rs. Ten Lakh in any of the financial year for the period under reference, he is entitled to avail benefit of Notification No. 06/2005-ST dated 01.03.2005.



BAN)

- (iii) The assessable value considered for issue of Show Cause Notices has been determined on assumption presumption ground. He rely on case law as reported at 2009 (14) STR 511 (Tri.-Del.) and 2018 (18) GSTL 152 (AAR-GST).
- 5. In reply to personal hearing fixed on 29.11.2022, the Appellant vide their letter dated 22.11.2022 reiterated the grounds of appeal and further submitted that no documents had been supplied by the Department as how the taxable value has been arrived. M/s. Chandroday was the "MSO" and providing such cable network service by using own name and not using any independent provider of the cable net work like the Appellant. The impugned order is not sustainable in the eyes of law. They were paying entertainment tax.
- 6. Personal hearing in the matter fixed on 29.12.2022. The Appellant vide their letter dated 14.12.2022 (received on 28.12.2022) informed that they were independent provider of taxable service having all the facility and technology to transmit the electronic waves and has not availed any kind of brand name of M/s. Chandroday and thus they are eligible for threshold limit under Notification No. 6/2005-Service Tax. They further stated that they do not desire the personal hearing in the matter.
- 7. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the Appeal Memorandums and oral as well as written submissions made by the Appellants. The issue to be decided in the present case is as to whether the impugned order confirming demand of Service Tax amount including Education Cess and S.H. Education Cess under Section 73 of the Act, along with interest and imposition of penalties under Section 76, 77(1)(a), 77(2) and 77(1)(c) of the Act is legally correct or otherwise.
- 8. I find that the adjudicating authority has confirmed the demand primarily on the ground that the Appellant as sub-cable operators have provided services under the Brand name of "M/s. Chandroray" and hence value- based exemption under Notification No. 06/2005-ST dated 01.03.2005 as amended is not available to them.
- 8.1 I find that the then Commissioner (Appeals) vide Order-In-Appeal No. 61 to 64/2013(BVR)SKS/Commr.(A)/Ahd dated 03.05.2013, in an identical issue, has dismissed the appeal filed by the department observing as under:-



"The contentions of the department is that the respondents had used the brand name of their respective MSO in transmitting the signals. In this regard I find that the signals which the respondent had re-transmitted were of different distributors which were transmitted by the respective MSO to them. I am of the considered opinion that these signals do not bear any brand name and style of the MSO. At the most it can be said that the signals are in the name and style of distributors of that film or programme. Therefore, contention of the department that the services provided by the respondents were with the brand name of their respective MSO is not acceptable. Therefore, appeals filed by the department for denying the benefit of the exemption under notification no. 6/2005-ST dated 01.03.2005 as amended and for imposing penalty under Section 76,77 & and 78 of the Finance Act, 1994 does not succeed."

held that the respondent sub-cable operators, were eligible for value-based exemption under Notification No. 6/2005-ST dated 01.03.2005, as amended by Notification No. 33/2012-S.T. dated 20.06.2012. The appeal filed by the revenue against above Order-in-Appeal have been dismissed by the Hon'ble Tribunal vide Order No. A/11410-11506/2016 dated 02.11.2016 considering the low revenue involved therein.

- 8.2 I also find that the then Commissioner (Appeals) vide Order-In-Original No. BHV-EXCUS-APP-000-019-2021-22 dated 01.04.2022 has already decided the matter in favour of Shri Chirag Harendrabhai Andhariya for the period April-2014 to March-2015, by allowing the benefit of Notification No. 06/2015-S.T. dated 01.03.2005, as amended. Accordingly, following the findings recorded in Order-In-Appeal dated 03.05.2013 as well as Order-In-Appeal dated 01.04.2022, I hold that services provided by the Appellant cannot be considered as provided under other's brand name, and hence, the benefit of value based exemption under Notification No. 6/2005-ST dated 01.03.2005, as amended vide Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012, is available to the Appellant.
- 9. In view of above discussions and findings, I allow the benefit of threshold limit as prescribed under Notification No. 6/2005-Service Tax dated 01.03.2005, as amended vide Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012, to the Appellant subject to the conditions prescribed therein.
- 10. I direct the Adjudicating Authority to calculate and convey the Service Tax liability of Appellant after allowing benefit of the Notification as mentioned in Para 9 supra within 30 days of receipt of this order. I also direct the Adjudicating

Any

Page 5 of 6

Authority to keep in mind the provisions of Para 2(viii) of the Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012 while calculating the Service Tax dated 2

- 11. Further, I uphold the impugned order for levy of interest on Service Tax upon the Appellant if he is liable to pay Service Tax as discussed in para 9.8.10. above. I also uphold the impugned order imposing penalties under Section 76. Section 77(1)(a) and Section 77(1)(c) of the Act on the Appellantain case the taxable value is more than threshold limit.
- 12. अपीसकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है ।
- 12. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

B. Ot

(शिव प्रताप सिंह)/(Shiv Pratap Singh), आयुक्त (अपीस)/Commissioner (Appeals)

By RPAD To, Superintendent Central GST (Appeals) Rajkot

To, M/s. Digvijaysinh P. Gohil, 75/A, Shantinagar, B/h Press Quarter, Shivparvati Street No. ¾, Bhavnagar. प्रति, मे. दिग्विजयसिंह पी. गोहील, 75/A, शांतिनगर, प्रेस क्वार्टर के पीछे, शिवपार्वती

शेरी नंबर ३-४, आवनगर .

प्रति:-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुरूक, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) प्रधान आनुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आनुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अपर/सर्वुक्त आवृक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) सहाबक आबुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर-। मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6) गार्ड फ्राइल ।

